(b) if go, what will be the extent of Central assistance in the expenditure likely to be incurred?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) No, Sir.

(b) The Central Government had assured the Government of Assam of financial assistance upto Rs. 25 crores; 50 per cent by way of grant-in-aid and 50 per cent by way of loan for the construction of new Capital.

आदिवासी परिवारों का पुनर्वास

*385. श्री नन्द किशोर भट्ट :
श्री बलराम दास :
श्री सवाई सिंह सिसोदिया :
श्रीमती रत्न कुमारी :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डाकारण्य परियोजना के परालकोट क्षेत्र में अब तक कितने आदिवासी परिवारों को बसाया गया है ; और

(ख) ऐसे कितने परिवार और हैं जिन्हें उक्त क्षेत्र में अभी बसाया जाना है; और उनके कब तक बसाये जाने की संभावना है ?

Rehabilitation of Tribal families

*385. SHRI N. K. BHATT: SHRI BALRAM DAS: SHRI SAWAISINGH SISODIA: SHRIMATI RATAN KUMARI:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of tribal families which have so far been rehabilitated in the Paralkote Zone of the Danda karanya Project; and

(b) the number of families which still remain to be rehabilitated in the said area and by when they are likely to be rehabilitated?]

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) दण्डाकारण्य परियोजना द्वारा दी गई 25 प्रतिशत उद्धार की गई भूमि पर परालकोट जोन में 343 आदिवासी परिवारों को अभी तक बसाया जा चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अब उस जोन में और परिवार नहीं बसाए जाएंगे। परन्तु आदिवासी भाव के रूप में दण्डाकारण्य परियोजना द्वारा भूमि उद्धार तथा पुनर्वास के सम्बन्ध में दी गई राशि को समेकित आदिवासी विकास परियोजना तथा परालकोट जोन में रह रही आदिवासी जनसंख्या के समस्त विकास के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

f[THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKAN-DAS BAKHT): (a) and (b) On the 25 per cent of the reclaimed land released by the Dandakaranya Project, 343 tribal families have so far been settled in the Paralkote Zone. The Government of Madhya Pradesh have decided not to settle any more families in that Zone but to utilize the funds provided by the Dandakaranya Project towards the cost of reclamation of land and settlement in respect of the tribal quota for financing the Integrated ribal Development Project and on the overall development of the tribal population living in the Paralkote Zone.]

t[ ] English translation.